राजेंद्र सिंह

बनाम

पंजाब राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 2321/2009)

26 फरवरी, 2015

[न्यायाधिपति टी. एस. ठाकुर, न्यायाधिपति आर. एफ. नरीमन और न्यायाधिपति प्रफुल्ल सी. पंत]

दंड संहिता, 1860 – धारा 304 बी - दहेज हत्या - निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्धि - माना गया: मामले के तथ्यों से यह साबित होता है कि यह दहेज हत्या का मामला था - दोषसिद्धि बरकरार रखी गई।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 - धारा 2 - दहेज - धारित का अर्थ: अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति द्वारा विवाह के समय/पहले/किसी भी समय मांगी गई कोई धन/संपत्ति/मूल्यवान सुरक्षा जो उचित रूप से संबंधित हो। एक विवाहित महिला की मृत्यु, विवाह के संबंध में होगी, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा इंगित न किया गया हो।

शब्दों और वाक्यांशों:

'दहेज' - का अर्थ, दहेज की धारा 2 के संदर्भ में

निषेध अधिनियम, 1961.

"उसकी मृत्यु से तुरंत पहले" - का अर्थ, आईपीसी की धारा 304 बी के संदर्भ में -चर्चा की गई।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए माना:

1. धारा के तहत अपराध के चार तत्व हैं। आईपीसी की धारा 304 बी और उनके अनुसार कहा जाता है कि (ए) किसी महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई होगी या उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्यथा हुई होगी; (बी) ऐसी मृत्यु उसकी शादी के सात साल के भीतर हुई होगी; (सी) उसकी मृत्यु से ठीक पहले, वह अपने पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार हुई होगी; और (डी) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के संबंध में होना चाहिए। [पैरा9) [846-बी-डी]

अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य, 2010 (7) एससीआर 1119= (2010) 12 एस. सी. सी. 350; बचनी देवी और अन्य बनाम हरियाणाराज्य 2011 (2) एससीआर 627 = (2011) 4 एससीसी 427, पठान हुसैन बाशा बनाम ए. पी. राज्य 2012 (7) एस. सी. आर. 290 = (2012) 8 एस. सी. सी. 594, कुलवंत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 2013 (5) एससीआर 604 = (2013) 4 एससीसी177, सुरिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2014) 4 एस. सी. सी. 129, रमिंदर सिंह बनाम पजाब राज्य (2014)12 एस सी सी 582 , सुरेश सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2013) 16 एससीसी 353, शेर सिंह बनाम हरियाणा 2015 1स्केल 250-पर निर्भर था।

2. आईपीसी की धारा 304 बी में आने वाले शब्द "जल्द" का अर्थ "तत्काल" नहीं है। जिस महान सामाजिक बुराई के कारण धारा 304 बी को लागू किया गया, उसे ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष और व्यावहारिक निर्माण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अभिव्यक्ति एक सापेक्ष अभिव्यक्ति है। दिन या महीने वह नहीं हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए। समय अंतराल हर मामले में अलग-अलग हो सकता है। बस इतना जरूरी है कि आईपीसी की धारा 304 बी के तहत दहेज की मांग बासी नहीं होनी चाहिए, बल्कि विवाहित महिला की मृत्यु का निरंतर कारण होनी चाहिए। [पैरा 23) [858-बी-सी]

सुरिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2014) 4 एस. सी. सी 129; शेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2015 (1) स्केल 250 पर भरोसा किया।

दिनेश बनाम हरियाणा राज्य, 2014 (5) स्केल 641 -सही कानून नहीं है।

3. आईपीसी की धारा 304 बी एक कठोर प्रावधान है, जिसका उद्देश्य खतरनाक स्तर की सामाजिक बुराई का मुकाबला करना है। निष्पक्ष, व्यावहारिक और सामान्य ज्ञान की व्याख्या देने के लिए ताकि संसद द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को पूरा किया जा सके, यह माना जाता है कि दहेज निषेध अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति द्वारा शादी के समय या उससे पहले या बाद में किसी भी समय मांगी गई कोई भी धन या संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा, जो एक विवाहित महिला की मृत्यु से उचित रूप से जुड़ी हुई है, आवश्यक रूप से संबंधित होगी विवाह के साथ या उसके संबंध में, जब तक कि किसी दिए गए मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से अन्यथा इंगित न करें। [पैरा 13 और 20] (847-एच, 854.-जी-एच; 855-ए-बी)

एम. नारायणन नांबियार बनाम केरल राज्य, 1963 सप(2) एस. सी. आर. 724; स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम निदेशालय प्रवर्तन 2005 (1) पूरक एससीआर 49 = (2005) 4 एससीसी 530 अनुसरण किया।

अप्पासाहेब बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007 (1) एससीआर 164=(2007) 9 एससीसी 721; विपिन जयसवाल बनाम आंध्रप्रदेश राज्य 2013 (3) एससीआर 449 =2013 (3) एस सी सी 684 - सही कानून नहीं माना गया।

बचनी देवी बनाम हरियाणा राज्य 2011 (2) एससीआर 627 = (2011) 4 एससीसी 427; कुलवंत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 2013(5) एससीआर 604 =(2013) 4 एससीसी 177; सुरिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2014) 4 एससीसी

129; और रमिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 12 एससीसी 582; के. प्रेमा एस. राव और अन्य बनाम यादला श्रीनिवास राव और अन्य 2002 (3) पूरक एससीआर 339 =(2003) 1 एससीसी 217; रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम 2004 (1) एससीआर 378 (2004) 3 एससीसी 199- संदर्भित।

4. वर्तमान मामले में, शादी के एक साल बाद ही पैसे की मांग की गई। शांति की भेंट के रूप में पिता ने बेटी को भैंसा दिया। शांति प्रस्ताव का कोई असर नहीं हुआ. मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया गया. वह अपने पिता के पास वापस गई और फिर से पैसे की मांग की। तब पिता अपने भाई और गांव के सरपंच के साथ वैवाहिक घर में यह अनुरोध करने गए कि उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। पिता ने उक्त व्यक्तियों को यह भी आश्वासन दिया कि उनकी पैसे की मांग पूरी की जाएगी। उसकी मृत्यु से पंद्रह दिन पहले, मृतिका अपने नए परिवार द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर फिर से अपने माता-पिता के घर गई। फिर उसे जहर देकर मौत मान लिया जाएगा। मृतक के पिता की जिरह ने किसी भी तरह से उसकी गवाही को हिला नहीं दिया है। इसलिए, नीचे दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों को बरकरार रखा जाता है। [पैरा 26) [858- एच;859-ए-डी]

वाद कानून संदर्भित

2010(7)एस सी आर 1119	संदर्भित	पैरा 10
2011(2)एस सी आर 627	संदर्भित	पैरा 10
2012(7)एस सी आर 290	संदर्भित	पैरा 10
2013(5)एस सी आर 604	संदर्भित	पैरा 10
2014(12)एस सी सी 582	संदर्भित	पैरा 10
2013(16)एस सी सी 353	संदर्भित	पैरा 10

2015 1स्केल 250	संदर्भित	पैरा 10, 22
2007(1)एस सी आर 164	कानून सही नही माना	पैरा 11, 20
2013(3)एस सी आर 449	कानून सही नही माना	पैरा 12, 20
2013(5)एस सी आर 604	संदर्भित	पैरा 12
(2014)4 एस सी सी 129	संदर्भित	पैरा 12
(2014)12 एस सी सी 582	संदर्भित	पैरा 12
1963 पूरक (2)एस सी आर 724	अनुसरण किया	पैरा 14
2005(1)पूरक एस सी आर 49	अनुसरण किया	पैरा 15
2002(3)पूरक एस सी आर 339	संदर्भित	पैरा 19
2004(1)एस सी आर 378	संदर्भित	पैरा 19
2014(4)एस सी सी 129	भरोसा किया	पैरा 21
2014(5)स्केल 641	कानून सही नही माना	पैरा 24

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2009 की आपराधिक अपील संख्या 2321

1998 की आपराधिक संख्या 84-एसबी में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 10.12.2008 से

अपीलकर्ता की ओर से सुधीर वालिया, निहारिका अहलूवालिया, डॉ. अभिषेक अत्रे।

प्रतिवादी की ओर से जयंत के. सूद, जसलीन चहल, एएजी, कुलदीप सिंह।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

न्यायाधिपति आर.एफ.नरीमन

1. इस मामले के तथ्य इस देश की महिलाओं के खिलाफ सदियों से चली आ रही दो बड़ी सामाजिक बुराइयों में से एक से संबंधित सवाल उठाते हैं। हमारे सामने प्रस्तुत तथ्यों में, एक युवा महिला ने उस परिवार द्वारा बार-बार पैसे की मांग किए जाने के कारण कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसमें उसे अपनी पहचान का विलय करना था। सती प्रथा और दहेज हत्या ने इस देश को सदियों से परेशान किया है। सती - एक विधवा को उसके पति की चिता में जलाने के लिए भेजने की प्रथा - पहली बार 1829 और 1830 में ब्रिटिश शासन के तहत बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरल सर चार्ल्स नेपियर, कमांडर के तहत गैरकानूनी घोषित की गई थी। ऐसा माना जाता है कि 1859 और 1861 के बीच भारत में ब्रिटिश सेना के प्रमुख ने उन हिंदू पुजारियों से कहा था जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने के बारे में उनसे शिकायत की थी कि "विधवाओं को जलाना आपकी प्रथा है लेकिन मेरे देश में, जब कोई व्यक्ति किसी महिला को जिंदा जलाते हैं, हम उन्हें फाँसी देते हैं और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लेते हैं। इसलिए, हम दोनों अपनी राष्ट्रीय रीति-रिवाजों के अनुसार कार्य करें।"

2. सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम, 1987 को संसद द्वारा पारित करने और सती प्रथा से संबंधित विभिन्न अपराधों को निर्धारित करने और विशेष अदालतों द्वारा ऐसे अपराधों की सुनवाई करने में कई साल लग गए। हालाँकि, इस अपील में हमारा सामना दूसरी बड़ी समस्या, दहेज हत्या से होता है। जहां तक दहेज पर रोक का सवाल है, संसद ने बहुत पहले दहेज निषेध अधिनियम, 1961 लागू करके प्रतिक्रिया दी थी, जिसके तहत दहेज देने या लेने पर दंड के रूप में न्यूनतम सजा निर्धारित की गई थी। हालाँकि, दहेज हत्या के विशिष्ट खतरे को 1986 में एक नए प्रावधान - दंड संहिता में धारा 304 बी के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के एक और नए प्रावधान की शुरूआत से निपटा गया था। ये दो अनुभाग इस प्रकार हैं:

"304-बी. दहेज मृत्यु.-(1) जहां एक महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या उसकी शादी के सात साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अलावा होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले वह थी दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में अपने पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन, ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

स्पष्टीकरण .-इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई भी दहेज हत्या करेगा उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।"

"113-बी. दहेज हत्या के बारे में धारणा.-जब सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने एक महिला की दहेज हत्या की है और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले ऐसी महिला के साथ ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, या दहेज की किसी भी मांग के संबंध में, न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या का कारण बना दिया है।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304-बी में है।"

3: वर्तमान अपील के तथ्यों पर वापस आते हुए, एक युवा महिला, सलविंदर कौर की शादी अपीलकर्ता राजिंदर सिंह से वर्ष 1990 में हुई थी। 31 अगस्त, 1993 को, शादी के चार साल के भीतर, सलविंदर कौर ने एल्युमीनियम का सेवन कर लिया। फॉस्फाइड, जो एक कीटनाशक है, जिसके परिणामस्वरूप उसका युवा जीवन ख़त्म हो गया। उसी दिन पति, उसके बड़े भाई और बड़े भाई की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। विचारण न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष के साक्ष्यों की जांच करने के बाद, अपीलकर्ता के बड़े भाई और उसकी पत्नी को बरी कर दिया, लेकिन अपीलकर्ता को धारा 304 बी के तहत दोषी ठहराया और उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जो कि दोषी ठहराए जाने पर सुनाई जाने वाली न्यूनतम सजा है। उक्त धारा के तहत अपराध. यह विशेष रूप से पीडब्लू2 - मृतक महिला के पिता कमल सिंह, पीडब्लू-3 - गुलज़ार सिंह, उनके बड़े भाई और पीडब्लू-4 - गांव के सरपंच बलविंदर सिंह के साक्ष्य की जांच करने के बाद किया गया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले के माध्यम से दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

4. इस अपील के प्रयोजन के लिए मृत महिला के पिता के साक्ष्य को प्रस्तुत करना पर्याप्त है जिसे नीचे की दो अदालतों ने स्वीकार कर लिया है।

"मेरी तीन बेटियाँ और दो बेटे हैं, परमजीत कौर, मंजीत कौर और सलविंदर कौर मेरी बेटियाँ हैं सलविंदर कौर मेरी बेटी की शादी राजिंदर सिंह निवासी बथवाला से हुई थी। उसकी मृत्यु से चार साल पहले उसकी शादी राजिंदर सिंह से हुई थी। एक साल बाद

शादी के बाद मेरी बेटी मेरे पास आई और बताया कि अदालत में मौजूद उसके पति राजिंदर सिंह, देवर दविंदर सिंह और गुरमित कौर घर बनाने के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। उसने मुझे यह भी बताया कि वे झगड़ा कर रहे थे पैसे की उक्त मांग के लिए। अपनी बेटी की शादी के समय, मैंने अपनी हैसियत के अनुसार पर्याप्त दहेज दिया था। मैंने अपनी बेटी से कहा कि इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। हालाँकि, मैंने उसे भैंस दे दी मेरी बेटी को ससुराल ले जाने के लिए कहा और सास-ससुर के साथ रहने के लिए कहा। 7/8 महीने के बाद, जब मेरी बेटी के साथ आरोपियों ने फिर से दुर्व्यवहार किया, तो वह मेरे पास आई और फिर से पैसे की मांग की। अदालत में मौजूद आरोपी मेरी बेटी से इस वादे के साथ वापस आने की मांग कर रहे थे कि मैं जल्द ही उससे मिलने आऊंगा और अगले दिन, मैं अपने भाई गुइजर सिंह, तत्कालीन सरपंच बलविंदर सिंह और पूर्व-सरपंच हजूरा सिंह के साथ अदालत गया। आरोपी का घर गांव बाथावाल में है। अभियुक्त के घर पहुंचने पर न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण एवं मेरी पुत्री के ससुर अपने घर पर उपस्थित थे। मेरे दामाद हरजिंदर सिंह, गुरमित कौर और दविंदर सिंह भी मौजूद थे। मैंने उन सभी से अनुरोध किया कि वे पैसे की मांग को लेकर मेरी बेटी से झगड़ा न करें। मैंने आरोपियों को यह भी आश्वासन दिया कि मैं फसल कटाई के समय उन्हें उक्त राशि का भुगतान कर दूंगा। आरोपी पैसे की मांग को लेकर अड़े रहे। मेरी बेटी सलविंदर कौर अपनी मृत्यु से 15 दिन पहले मेरे घर आई थी। मैंने अपनी बेटी को फिर से आश्वस्त किया कि मैं फसल काटने के बाद पैसे जरूर चुकाऊंगा। मुझसे पैसे न मिलने पर सलविंदर कौर खुश नहीं थी। आरोपियों ने उसके साथ दुव्र्यवहार किया। सलविंदर कौर की मौत के बाद, वी बथवाला के सदस्य पंचायत हरभजन सिंह और आरोपी दविंदर सिंह मेरे घर आए और बताया कि मेरी बेटी की कुछ जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई है और मुझे शव का अंतिम संस्कार करने के लिए उनके साथ जाने के लिए कहा गया।

5. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। अपीलकर्ता के वकील ने करनैल सिंह की जिरह पर भरोसा किया जो नीचे दिया गया है: -

> "मुझे नहीं पता कि देविंदर सिंह का अलग हिस्सा था या नहीं मेरी बेटी अपनी शादी के 5/6 महीने बाद पहली बार मेरे पास आई थी, लेकिन उसने आरोपी व्यक्तियों के आचरण के बारे में मुझसे कोई शिकायत नहीं की। उसने मुझसे शिकायत की लगभग एक साल बाद ही उसने मुझसे कहा था कि वे एक संयुक्त घर बनाना चाहते हैं और उस उद्देश्य के लिए पैसे लाने के लिए कहा था। हालांकि मैंने इस उद्देश्य के लिए उसे कोई पैसा नहीं दिया। पंचायत में कभी कोई लिखित शिकायत नहीं की गई। मैंने बलविंदर सिंह से इस बारे में कभी बात नहीं की। यह कहना गलत है कि मेरी बेटी से कभी पैसे की मांग नहीं की गई या मैंने झूठी गवाही दी है।"

6. इसके आधार पर, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि विवाह से जुड़ी मांग के बीच आवश्यक संबंध टूट गया था और तथ्य यह है कि चूंकि शुरू में शिकायतें लंबे अंतराल पर की गई थीं, इसलिए धारा 304 बी के तहत कोई अपराध नहीं कहा जा सकता था। बाहर कर दिया। पंजाब राज्य के वकील ने दोनों अदालतों के निष्कर्षों को दोहराया और उच्च न्यायालय के फैसले के समर्थन में तर्क दिया।

7. धारा 304 बी के तहत अपराध को आकर्षित करने का प्राथमिक घटक यह है कि एक महिला की मृत्यु "दहेज मृत्यु" होनी चाहिए। "दहेज" को दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 द्वारा परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"2. "दहेज" की परिभाषा - इस अधिनियम में, "दहेज" का अर्थ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा-

(ए) विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष से; या

(बी) विवाह के किसी भी पक्ष के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, विवाह के किसी भी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, या उससे पहले [या विवाह के बाद किसी भी समय] [उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में , लेकिन इसमें उन व्यक्तियों के मामले में मेहर या महर शामिल नहीं है जिन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) लागू होता है।

स्पष्टीकरण I.-[***]

स्पष्टीकरण II.-अभिव्यक्ति "मूल्यवान सुरक्षा" का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 30 में है।"

8. इस अनुभाग के अवलोकन से पता चलता है कि इस परिभाषा को छह अलग-अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1) दहेज में सबसे पहले कोई संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा शामिल होनी चाहिए - शब्द "कोई भी" व्यापक शब्द है और इसलिए, इसमें संपत्ति और किसी भी प्रकार की मूल्यवान सुरक्षा शामिल होगी।

2) ऐसी संपत्ति या सुरक्षा दी जा सकती है या देने पर सहमति भी दी जा सकती है। इसलिए, ऐसी संपत्ति या सुरक्षा का वास्तविक दान आवश्यक नहीं है।

3) ऐसी संपत्ति या प्रतिभूति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जा सकती है या देने पर सहमति व्यक्त की जा सकती है।

4) ऐसा देना या देने पर सहमति न केवल विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से, बल्कि किसी भी पक्ष के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी हो सकती है। देखा गया कि जहां तक दहेज लेने या देने का अपराध करने के दोषियों का सवाल है, यह खंड फिर से अधिनियम की पहुंच को व्यापक बनाता है।

5) ऐसा देना या देने की सहमति किसी भी समय हो सकती है। यह विवाह के समय, उससे पहले या उसके बाद किसी भी समय हो सकता है। इस प्रकार, विवाह संपन्न होने के कई वर्ष बाद भी ऐसा हो सकता है।

6) ऐसा देना या लेना पक्षों के विवाह के संबंध में होना चाहिए। जाहिर है, दहेज निषेध अधिनियम द्वारा जिस सामाजिक बुराई से निपटने की मांग की गई है, उसके संदर्भ में "संबंध में" अभिव्यक्ति का अर्थ "संबंध में" या "संबंधित" होगा।

9. धारा 304 बी के तहत अपराध की सामग्री को कई निर्णयों में बताया और दोहराया गया है। ऐसी चार सामग्रियां हैं और उनके बारे में कहा जाता है:

(ए) किसी महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई होगी या उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्यथा हुई होगी;

(बी) ऐसी मृत्यु उसकी शादी के सात साल के भीतर हुई होगी;

(सी) उसकी मृत्यु से ठीक पहले, वह अपने पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार हुई होगी; और

(डी) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के संबंध में होना चाहिए।

10. यह निम्नलिखित निर्णयों में कहा गया कानून है:

अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य, (2010) 12 एससीसी 350 पृष्ठ 360-361 पर; बचनी देवी एवं अन्य. बनाम हरियाणा राज्य, (2011) 4 एससीसी 427 पर 431, पठान हुसैन बाशा बनाम स्टेट ऑफ ए.पी., (2012) 8 एससीसी 594 पर 599, कुलवंत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2013) 4 एससीसी 177 पर 184-185, सुरिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2014) 4 एससीसी 129 पर 137, रमिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 12 एससीसी 582 पर 583, सुरेश सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 16 एससीसी 353 पर 361, शेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2015 स्केल 250 पर 262।

11. इस न्यायालय ने कभी-कभी अलग-अलग स्वरों में बात की है। परिभाषा के अनुसार "दहेज" के अंतर्गत क्या आएगा और "उसकी मृत्यु से ठीक पहले" अभिव्यक्ति का क्या मतलब है। अप्पासाहेब बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2007) 9 एससीसी 721 में, इस न्यायालय ने दहेज की परिभाषा को सख्ती से समझा, क्योंकि यह धारा 304 बी का हिस्सा है जो एक दंडात्मक क़ानून का हिस्सा है। अदालत ने माना कि खर्चों को चुकाने के लिए पैसे की मांग की गई थी एक युवा पत्नी द्वारा अपने पिता से की गई खाद की मांग दहेज की परिभाषा से बाहर होगी। इस न्यायालय ने कहा:

> "कुछ वित्तीय तंगी के कारण या कुछ जरूरी घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए या खाद खरीदने के लिए पैसे की मांग को दहेज की मांग नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उक्त शब्द को आम तौर पर समझा जाता है। इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह नहीं दिखाते हैं कि दहेज निषेध अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित "दहेज" की कोई भी मांग अपीलकर्ताओं द्वारा की गई थी क्योंकि जो कथित तौर पर मांगा गया था वह घरेलू खर्चों को पूरा करने और खाद खरीदने के लिए कुछ पैसे थे। (पेज 727 पर)

12. यह निर्णय कम से कम चार अन्य निर्णयों में प्रतिष्ठित था (देखें: बचनी देवी बनाम हरियाणा राज्य (2011) 4 एससीसी 427 पृष्ठ 432 से 434 पर; कुलवंत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2013) 4 एससीसी 177 पृष्ठ 185 पर; सुरिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2014) 4 एससीसी 129 पृष्ठ 139 से 141 पर और रमिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 12 एससीसी 582 पृष्ठ 586 पर। हालाँकि, इस फैसले का पालन विपीन जायसवाल बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2013) 3 एससीसी 684 पेज 687-688 पर मामले में किया गया था।

13. दहेज की परिभाषा के वास्तविक निर्माण और परिणामस्वरूप धारा 304 बी के तहत अपराध की सामग्री पर पहुंचने के लिए, हमें पहले यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के क़ानून की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। यह स्पष्ट है कि धारा 304 बी एक कठोर प्रावधान है, जो खतरनाक स्तर की सामाजिक बुराई से निपटने के लिए है। क्या यह तर्क दिया जा सकता है कि यह एक दंडात्मक क़ानून है और इसलिए, इसकी भाषा में अस्पष्टता के मामले में, इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए?

14. इसका उत्तर इस न्यायालय के दो अग्रणी निर्णयों में पाया जाना है। एम. नारायणन नांबियार बनाम केरल राज्य, 1963 पूरक(2) एससीआर 724 में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1) (डी) का अर्थ लगाने के लिए कहा गया था। , एक दंड विधान, न्यायाधिपति सुब्बा राव द्वारा कहा गया:

> "प्रस्तावना इंगित करती है कि अधिनियम पारित किया गया था क्योंकि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अधिक प्रभावी प्रावधान बनाना समीचीन था। लंबे शीर्षक के साथ-साथ प्रस्तावना से

संकेत मिलता है कि अधिनियम उक्त सामाजिक बुराई यानी रिश्वतखोरी को कम करने के लिए पारित किया गया था। लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार। रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। यह तथ्य कि "रिश्वत" शब्द के अलावा "भ्रष्टाचार" शब्द का प्रयोग किया गया है, यह दर्शाता है कि इस कानून का उद्देश्य रिश्वतखोरी के अलावा अन्य बुराईयों से भी निपटना था। मौजूदा कानून यानी दंड संहिता को हमारे देश की सार्वजनिक सेवा को खराब करने वाली रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की बढ़ती बुराई को खत्म करने या यहां तक कि नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त पाया गया। प्रावधानों में मोटे तौर पर जनता द्वारा किए गए भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और 165 के तहत मौजूदा अपराध शामिल हैं। सेवकों और अभियुक्तों के विरुद्ध अनुमानित साक्ष्य का एक नया नियम बनाएं। यह अधिनियम लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार का एक नया अपराध भी बनाता है, हालांकि कुछ हद तक यह पहले से मौजूद अपराधों पर ओवरलैप करता है और आपराधिक न्यायशास्त्र के प्रसिद्ध सिद्धांतों के विपरीत एक खंडन योग्य धारणा बनाता है। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करके ईमानदार लोक सेवकों को उत्पीड़न से बचाना भी है कि उनके खिलाफ जांच केवल विशेष स्थिति के पुलिस अधिकारियों द्वारा ही की जा सकती है और सरकार या अन्य उपयुक्त अधिकारी की मंजूरी को उनके अभियोजन के लिए पूर्व शर्त बनाकर।

चूंकि यह सार्वजनिक हित में सोचा गया एक सामाजिक रूप से उपयोगी उपाय है, इसलिए इसे उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए ताकि वांछित उद्देश्य हासिल किया जा सके, यानी लोक सेवकों के बीच

भ्रष्टाचार को रोका जा सके और उनके बीच ईमानदार लोगों के उत्पीड़न को रोका जा सके।

डाइक बनाम इलियट में न्यायिक समिति का एक निर्णय, जिसे विद्वान वकील ने निर्माण के लिए सहायता के रूप में उद्धृत किया है, सिद्धांत को स्पष्ट रूप से बताता है और इसलिए इसे निकाला जा सकता है: बोर्ड के लिए बोलते हुए लॉर्ड जस्टिस जेम्स पृष्ठ 191 पर टिप्पणी करते हैं:

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी दंडात्मक क़ानूनों को सख्ती से समझा जाना चाहिए, यानी, अदालत को यह देखना चाहिए कि जिस चीज़ पर अपराध के रूप में आरोप लगाया गया है वह इस्तेमाल किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ के भीतर है, और किसी भी धारणा पर शब्दों को तनाव नहीं देना चाहिए एक चूक हो गई है, कि एक कारण चूक हो गई है, कि बात इतनी स्पष्ट रूप से शरारत के भीतर है कि अगर सोचा जाए तो इसे शामिल करने का इरादा रहा होगा। दूसरी ओर, जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसे यह कहने का अधिकार है कि हालांकि शब्दों के भीतर आरोपित की गई बात अधिनियम की भावना के भीतर नहीं है। लेकिन जहां बात को शब्दों के भीतर और भावना के भीतर लाया जाता है, वहां दंडात्मक अधिनियम को किसी भी अन्य उपकरण की तरह, उचित सामान्य अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। इस्तेमाल की गई भाषा, और न्यायालय को दंडात्मक क़ानून की भाषा में कोई संदेह या अस्पष्टता नहीं ढूंढनी है या नहीं बनानी है, जहां ऐसा संदेह या अस्पष्टता स्पष्ट रूप से किसी अन्य उपकरण में उसी भाषा में नहीं पाई जाएगी या बनाई जाएगी।"

हमारे विचार में यह परिच्छेद, यदि हम ऐसा कह सकें, एक दंडात्मक प्रावधान के निर्माण के नियम को सही दृष्टिकोण से दोहराता है।"

15. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2005) 4 एससीसी 530 पृष्ठ 547 पर, 40 साल बाद एक अन्य संविधान पीठ को इस बात का सामना करना पड़ा कि क्या किसी कॉर्पोरेट निकाय पर उन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिनके लिए कारावास की सजा दी जाती है। अनिवार्य 3:2 के बहुमत से, प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया गया। न्यायाधिपति बालाकृष्णन: आयोजित:

"23. अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि क़ानून में दंडात्मक प्रावधान को सख्ती से समझा जाना चाहिए। तोलाराम रेलुमल बनाम बॉम्बे राज्य [(1955) 1 एससीआर 158: 1954 सीआरआई एलजे 1333] एससीआर पृष्ठ 164 पर संदर्भ दिया गया था। और गिरधारी लाल गुप्ता बनाम ओ.एच. मेहता [(1971)3 एससीसी 189: 1971 एससीसी (सीआरआई) 279]। यह सच है कि सभी दंडात्मक क़ानूनों को सख्ती से इस अर्थ में समझा जाना चाहिए कि अदालत को यह देखना चाहिए कि जिस चीज़ पर आरोप लगाया गया है अपराध इस्तेमाल किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ के भीतर है और शब्दों को किसी भी धारणा पर तनाव नहीं देना चाहिए कि एक चूक हुई है कि बात इतनी स्पष्ट रूप से शरारत के भीतर है कि इसे शामिल करने का इरादा रहा होगा और यदि सोचा गया तो शामिल किया गया होगा अन्य सभी क़ानूनों की तरह सभी दंड प्रावधानों को अधिनियम में व्यक्त विधायी इरादे के अनुसार उचित रूप से समझा जाना चाहिए। यहां, कॉर्पोरेट निकायों पर उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाने का विधायी इरादा स्पष्ट और स्पष्ट है और क़ानून का

इरादा कभी भी दोषमुक्ति का नहीं था उन पर मुकदमा चलाने से. यह सामान्य ज्ञान के प्रति सरासर हिंसा है कि विधायिका का इरादा छोटे और मूर्खतापूर्ण अपराधों के लिए कॉर्पोरेट निकायों को दंडित करने और बड़े और गंभीर आर्थिक अपराधों के लिए अभियोजन की प्रतिरक्षा बढ़ाने का था।

24. आधुनिक समय में सख्त निर्माण और अधिक मुक्त निर्माण के बीच का अंतर गायब हो गया है और अब ज्यादातर सवाल यह है कि "क़ानून का सच्चा निर्माण क्या है?" क्रेज़ ऑन स्टैच्यूट लॉ, 7 वें संस्करण में एक अंश। निम्नलिखित प्रभाव पढ़ता है:

"सभी वर्गों के क़ानूनों के संबंध में सख्त और उदार निर्माण के बीच का अंतर लगभग गायब हो गया है, इसलिए सभी क़ानून, चाहे दंडात्मक हों या नहीं, अब काफी हद तक समान नियमों द्वारा माने जाते हैं। 'सभी आधुनिक अधिनियम न्यायसंगत के संबंध में तैयार किए गए हैं साथ ही कानूनी सिद्धांत भी।' 'सौ साल पहले,' ल्योंस मामले में अदालत ने कहा [ल्योंस बनाम ल्योंस, 1858 बेल सीसी 38: 169 ईआर 1158], 'कानूनों को पूरी तरह से सटीक होना आवश्यक था और अधिनियम के उचित निर्माण का सहारा नहीं लिया गया था , और इस तरह अपराधियों को अक्सर भागने की अनुमति दी जाती थी। यह संसद के अधिनियमों की व्याख्या करने का वर्तमान तरीका नहीं है। अब उन्हें विधायिका के सही अर्थ और वास्तविक इरादे के संदर्भ में समझा जाता है।"

उसी पुस्तक के पृष्ठ 532 पर, सेडगविक की टिप्पणियों को इस प्रकार उद्धृत किया गया है:

> "सिद्धांत का अधिक सही संस्करण यह प्रतीत होता है कि इस वर्ग के क़ानूनों को विधायिका के इरादे के अनुसार निष्पक्ष रूप से समझा और ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए, एक ओर अनुचित गंभीरता के बिना या दूसरी ओर संदेह के मामलों में अनुचित उदारता के बिना। दया की ओर झुकाव रखने वाली अदालतें।"

16. न्यायाधिपति बालकृष्णन से सहमति जताते हुए न्यायाधिपति धर्माधिकारी ने कहा:

> "36. दंडात्मक क़ानूनों के सख्त निर्माण की आवश्यकता वाली व्याख्या का नियम किसी प्रावधान के संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण निर्माण की गारंटी नहीं देता है ताकि अपराधी के बचने के लिए कमियां छोड़ी जा सकें (देखें)
>
> मुरलीधर मेघराज लोया बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1976) 3 एससीसी 684 : 1976 एससीसी (सीआरआई) 493]। एक दंडात्मक क़ानून की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि कमी से बचा जा सके और शरारत को दबाया जा सके और हेडन के मामले [(1584) 3 सह प्रतिनिधि 7ए: 76 ईआर 637] में नियम के आलोक में एक उपाय आगे बढ़ाया जा सके एक सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण दंडात्मक क़ानून की प्रयोज्यता के प्रश्न को हल करने के लिए सख्त निर्माण के नियम से इंकार नहीं किया जाता है। (ए.पी. राज्य बनाम बथु प्रकाश राव [(1976) 3 एससीसी 301: 1976 एससीसी(आपराधिक) 395] और

वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों पर जीपी सिंह भी देखें, 9वां संस्करण, 2004, अध्याय 11, सारांश 3 पर पृष्ठ 754 से 756.)"

17. और न्यायाधिपति अरुण कुमार ने उपरोक्त दोनों न्यायाधीशों से सहमति जताते हुए, इस न्यायालय के पहले के दो निर्णयों का निम्नानुसार पालन किया: -

"49. बैरम कुमावत बनाम भारत संघ [(2003) 7 एससीसी 628], जिसमें मैं एक पक्ष था, के फैसले में इस न्यायालय की एक और तीन-न्यायाधीश पीठ ने वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों के संदर्भ में टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 635) , पैरा 23)

"23. इसके अलावा; यहां तक कि दंडात्मक क़ानून के संबंध में भी किसी भी संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण, शाब्दिक और शाब्दिक निर्माण को हमेशा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। कानून की व्याख्या अपराध के विषय-वस्तु और वस्तु के संबंध में की जानी चाहिए यह जिस कानून को हासिल करना चाहता है। कानून का उद्देश्य अपराधी को कानून के जाल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देना है। आपराधिक न्यायशास्त्र ऐसा नहीं कहता है।"

50. एम. ।।.जावली बनाम महाजन बोरवेल एंड कंपनी [(1997) 8 एससीसी 72: 1997 एससीसी (सीआरआई) 1239] में यह न्यायालय वर्तमान मामले जैसी ही स्थिति पर विचार कर रहा था। आयकर अधिनियम की धारा 278-बी के तहत एक कंपनी

धारा 276-बी के तहत किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है; क़ानून के प्रावधान के तहत कारावास की सज़ा दी जानी आवश्यक है और एक कंपनी एक

न्यायिक व्यक्ति होने के कारण इसके अधीन नहीं हो सकती है। यह माना गया कि स्पष्ट विसंगतिपूर्ण स्थिति को केवल अनुभाग की उचित व्याख्या से ही हल किया जा सकता है। न्यायालय ने देखा : (एससीसी पृष्ठ 78, पैरा 8)

"8. विधि आयोग की सिफ़ारिशों और क़ानूनों की व्याख्या के उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि धारा 276-बी को जो एकमात्र सामंजस्यपूर्ण संरचना दी जा सकती है, वह यह है कि कारावास और जुर्माने की अनिवार्य सज़ा है वहां लगाया जाएगा जहां इसे लगाया जा सकता है, अर्थात् उपरोक्त श्रेणियों (ii) और (iii) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों पर, लेकिन जहां इसे नहीं लगाया जा सकता है, अर्थात् किसी कंपनी पर, वहां जुर्माना ही एकमात्र सजा होगी।"

18. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, के. प्रेमा 5 राव और अन्य बनाम यडला श्रीनिवास राव और अन्य, (2003) 1 एससीसी 217 में, इस न्यायालय ने कहा:

"विधानमंडल ने दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करके विवाहित महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने और दंडित करने के लिए दंड कानून को और अधिक सख्त बना दिया है।"

19. रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम, (2004) 3 एससीसी199 में, दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, धारा 498 ए के संदर्भ में इस न्यायालय ने हेडन के मामले द्वारा अमर बनाए गए शरारत नियम को लागू किया और सीफोर्ड में लॉर्ड डेनिंग के फैसले का पालन किया। कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम आशेर, जहां विद्वान लॉ लॉर्ड ने कहा:

"उन्हें संसद की मंशा जानने के रचनात्मक कार्य पर काम करना चाहिए, और उन्हें यह न केवल क़ानून की भाषा से करना चाहिए, बल्कि उन सामाजिक परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए जिन्होंने इसे जन्म दिया और जो शरारत की इसे उपचार के लिए पारित किया गया था और फिर उसे लिखित शब्द को पूरक करना होगा ताकि विधायिका के इरादे को 'बल और जीवन' दिया जा सके।" (पृष्ठ 213 पर)

न्यायालय ने धारा 498ए में आने वाले 'पति' शब्द का व्यापक अर्थ देते हुए इसमें उन लोगों को भी शामिल किया है, जो पति होने का दिखावा करके भी किसी महिला के साथ संबंध बनाते हैं। न्यायालय ने कहा:

"...'पति' शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्ति को लगाना उचित होगा जो वैवाहिक संबंध में प्रवेश करता है और पति की ऐसी घोषित या नकली स्थिति के तहत संबंधित महिला के साथ क्रूरता करता है या किसी भी तरीके से उसके साथ जबरदस्ती करता है या प्रासंगिक प्रावधान धारा 304बी/498ए में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए, आईपीसी की धारा 498ए और 304बी के सीमित उद्देश्य के लिए विवाह की वैधता जो भी हो। ऐसी व्याख्या, जिसे उद्देश्यपूर्ण निर्माण के रूप में जाना और पहचाना जाता है, को लागू करना होगा इस प्रकृति के मामले में। 'पति' की परिभाषा का अभाव, विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को शामिल करने के लिए जो कथित रूप से विवाह करते हैं और ऐसी महिला के साथ सहवास करते हैं, 'पति' के रूप में अपनी भूमिका और स्थिति के कथित अभ्यास में उन्हें बाहर करने का कोई आधार नहीं है। आईपीसी की धारा 304बी या 498ए के दायरे से, उन प्रावधानों को लागू करने

वाले कानूनों के उद्देश्य और उद्देश्य के संदर्भ में देखा जाता है।" (पृष्ठ 210 पर)

20. यह देखते हुए कि जिस क़ानून के साथ हम काम कर रहे हैं उसकी निष्पक्ष, व्यावहारिक और सामान्य ज्ञान व्याख्या की जानी चाहिए ताकि संसद द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को पूरा किया जा सके, हमें लगता है कि अप्पासाहेब के मामले में निर्णय के बाद निर्णय आया विपीन जयसवाल का कानून सही ढंग से नहीं बताया गया है। इसलिए, हम घोषणा करते हैं कि दहेज निषेध अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति द्वारा विवाह के समय या उससे पहले या उसके बाद किसी भी समय किसी भी धन या संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की मांग की जाती है, जो एक विवाहित महिला की मृत्यु से उचित रूप से जुड़ा हुआ है। , आवश्यक रूप से विवाह के संबंध में या उसके संबंध में होगा, जब तक कि किसी दिए गए मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से अन्यथा इंगित न करें। अब धारा 304 बी के अन्य महत्वपूर्ण घटक पर आते हैं - "उसकी मृत्यु से ठीक पहले" का वास्तव में क्या मतलब है?

21. सुरिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2014) 4 एसईसी 129 में इस न्यायालय को यह कहना था:

> "17. इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-बी और आईपीसी की धारा 304-बी में भी "जल्द ही पहले" शब्द दिखाई देते हैं। इन धाराओं के तहत विचार की गई धारणाओं को क्रियान्वित करने के लिए, यह दिखाना आवश्यक है कि मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। इसलिए, "तुरंत पहले" शब्दों की व्याख्या महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि "बहुत पहले" कैसे? यह स्पष्ट

रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। क्रूरता या उत्पीड़न अलग-अलग मामलों में अलग-अलग होता है। यह लोगों की मानसिकता से संबंधित है जो व्यक्ति-दर-व्यक्ति में भिन्न होता है। क्रूरता मानसिक हो सकती है या यह शारीरिक हो सकती है। मानसिक क्रूरता भी विभिन्न रंगों की होती है। यह मौखिक या भावनात्मक हो सकती है जैसे किसी महिला का अपमान करना या उपहास करना या अपमानित करना। यह उसे या उसके प्रियजनों को चोट पहुंचाने की धमकी दे सकता है। यह उसे आर्थिक संसाधनों या जीवन की आवश्यक सुविधाओं से वंचित कर सकता है। यह उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। यह उसे बात करने की अनुमति नहीं दे सकता है बाहरी दुनिया। सूची उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है। शारीरिक क्रूरता किसी महिला की वास्तविक पिटाई या उसके व्यक्तित्व को दर्द और नुकसान पहुंचाना हो सकती है। क्रूरता और संबंधित उत्पीड़न की ऐसी हर घटना का महिला के दिमाग पर एक अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ मामले इतने गंभीर हो सकते हैं कि किसी महिला पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। कुछ ऐसे उदाहरण जो उसकी गरिमा को कम करते हैं, उसकी स्मृति में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। इसलिए, "अभी कुछ देर पहले" एक सापेक्ष शब्द है। भावनाओं के मामले में हमारे पास निश्चित सूत्र नहीं हो सकते। प्रत्येक मामले में समय अंतराल अलग-अलग हो सकता है। दहेज हत्या के प्रत्येक मामले की जांच करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

18. इस संबंध में हम कंस राज बनाम पंजाब राज्य ((2000) 5 एससीसी 207: 2000 एससीसी (सीआरआई) 935] में इस न्यायालय

के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं जहां इस न्यायालय ने "जल्द ही पहले" शब्द पर विचार किया था। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: (एससीसी पृष्ठ 222-23, पैरा 15)

"15. ... "जल्द ही पहले" एक सापेक्ष शब्द है जिस पर प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में विचार करना आवश्यक है और किसी भी समय-सीमा को तय करके कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह अभिव्यक्ति निकटता के परीक्षण विचार से गर्भवती है । "जल्द ही पहले" शब्द 'तत्काल पहले' शब्द का पर्याय नहीं है और यह 'तुरंत बाद' अभिव्यक्ति के विपरीत है जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114, चित्रण (ए) में इस्तेमाल और समझा गया है। इन शब्दों का अर्थ यह होगा कि बयान देने के समय और मृत्यु के बीच का अंतराल बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। यह उचित समय पर विचार करता है, जैसा कि पहले देखा गया है, प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के तहत समझा और निर्धारित किया जाना चाहिए। दहेज से होने वाली मौतों के संबंध में, परिस्थितियां मृतक के प्रति क्रूरता या उत्पीड़न के अस्तित्व को दर्शाना किसी विशेष उदाहरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आम तौर पर आचरण के एक पाठ्यक्रम को संदर्भित करता है। ऐसा आचरण समय की अवधि में फैल सकता है। यदि क्रूरता या उत्पीड़न या दहेज की मांग जारी रहती है , यदि ऐसे कथित उपचार और मृत्यु की तारीख से पहले, ऐसे उपचार की गैर-मौजूदगी को दर्शाने वाली कोई अन्य हस्तक्षेपकारी परिस्थिति रिकॉर्ड पर नहीं लाई जाती है, तो इसे 'मृत्यु से ठीक पहले' माना जाएगा। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे समय को

किसी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और परिणामी मृत्यु के बीच निकटतम और जीवंत संबंध को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है। ऐसी मांग और मृत्यु की तारीख के आधार पर दहेज की मांग, क्रूरता या उत्पीड़न का समय बहुत दूर नहीं होना चाहिए, जिसे इन परिस्थितियों में काफी पुराना माना जाएगा।"

इस प्रकार, ऐसी मांग और मृत्यु की तारीख के आधार पर दहेज की मांग, क्रूरता या उत्पीड़न के बीच कोई संबंध होना चाहिए। निकटता का परीक्षण लागू करना होगा. लेकिन, यह कोई कठोर परीक्षा नहीं है. यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और कानून के दायरे में अदालत के व्यावहारिक और संवेदनशील दृष्टिकोण की मांग करता है।"

22. शेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2015 (1) स्केल 250 में एक अन्य हालिया फैसले में, इस न्यायालय ने कहा:

"हम जानते हैं कि 'जल्द ही' शब्द धारा 304 बी में जगह पाता है; लेकिन हम इसके उपयोग की व्याख्या दिनों या महीनों या वर्षों के संदर्भ में नहीं करना पसंद करेंगे, बल्कि आवश्यक रूप से यह संकेत देते हुए कि दहेज की मांग बासी या असामान्य नहीं होनी चाहिए। अतीत का, लेकिन आईपीसी की धारा 304 बी के तहत मृत्यु या धारा 306 के तहत आत्महत्या का निरंतर कारण होना चाहिए। एक बार जब इन सहवर्ती लोगों की उपस्थिति स्थापित हो जाती है या अभियोजन पक्ष द्वारा दिखाई या साबित हो जाती है, यहां तक कि

संभावना की प्रबलता से भी, प्रारंभिक बेगुनाही की धारणा को आरोपी के अपराध की धारणा से बदल दिया जाता है, जिससे उस पर सबूत का भारी बोझ आ जाता है और उसे उचित संदेह से परे, अपने अपराध को खारिज करने वाले सबूत पेश करने की आवश्यकता होती है।" (पृष्ठ 262 पर)

23. हम इन दोनों निर्णयों में कही गई बातों का समर्थन करते हैं। दिन या महीने देखने लायक नहीं हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए कि "जल्द" शब्द का अर्थ "तत्काल" नहीं है। जिस महान सामाजिक बुराई के कारण धारा 304 बी को लागू किया गया, उसे ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष और व्यावहारिक निर्माण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अभिव्यक्ति एक सापेक्ष अभिव्यक्ति है। समय अंतराल हर मामले में अलग-अलग हो सकता है। बस इतना जरूरी है कि धारा 304 बी के तहत दहेज की मांग बासी नहीं होनी चाहिए बल्कि विवाहित महिला की मृत्यु का निरंतर कारण होनी चाहिए।

24. इस स्तर पर, दिनेश बनाम हरियाणा राज्य, 2014 (5) स्केल 641 में इस न्यायालय के हालिया फैसले पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है जिसमें कानून इस प्रकार कहा गया था:

"जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है, "सून बिफोर" शब्द एक सापेक्ष शब्द है, जिस पर प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में विचार किया जाना आवश्यक है और आवंटन का कोई भी समय तय करके कोई सीधा फॉर्मूला निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि "जल्द ही पहले" शब्द "तुरंत पहले" शब्द का पर्यायवाची है। "तुरंत पहले" शब्द के भीतर आने वाली अवधि का

निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अदालतों द्वारा निर्धारित किया जाता है। (पृष्ठ 646 पर)

25. हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि यह कानून का सही प्रतिबिंब नहीं है। "तुरंत पहले" का पर्याय "तत्काल पहले" नहीं है।

26. इस अपील के तथ्य स्पष्ट हैं। शादी के एक साल बाद ही पैसों की मांग की जाने लगी। शांति प्रस्ताव के रूप में पिता ने बेटी को एक भैंस दी थी। शांति प्रस्ताव का कोई असर नहीं हुआ. बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया. वह अपने पिता के पास वापस गई और फिर से पैसे की मांग की। फिर पिता अपने भाई के साथ चले गये। गांव के सरपंच ने वैवाहिक घर में अनुरोध किया कि पैसे की मांग के कारण बेटी के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। पिता ने उक्त व्यक्तियों को यह भी आश्वासन दिया कि उनकी पैसे की मांग पूरी की जाएगी और उन्हें उनके खेत की फसल कटने तक इंतजार करना होगा। अपनी मृत्यु से पंद्रह दिन पहले, सलविंदर कौर अपने नए परिवार द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर फिर से अपने माता-पिता के घर गईं। फिर जहर से मौत हुई. सलविंदर कौर के पिता की जिरह ने किसी भी तरह से उनकी गवाही को हिला नहीं दिया है। इसलिए तथ्यों के आधार पर, नीचे दी गई दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों को बरकरार रखा गया है। अपील खारिज की जाती है.

कल्पना के.त्रिपाठी अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।